Tamil Nadu in view of the vulnerability of the security of the region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALIT VIJAY SINGH): In view of the prevailing situation in the area, the Government issued orders to the Navy and the Coast Guard in May, 1990 to intensify their surveillance/patrolling of the Palk Bay/Palk Strait in order to check smuggling, illegal immigration and possible militant activties along the Tamil Nadu. Coast. These have been continuing in the area since then.

In order to provide for more effective surveillance/patrolling in the shallow waters off the Tamil Nadu Coast, two Naval Detachments have recently been established at Rameshwaram/Nagapattinam with hired trawlers. Besides these, the CRPF have also been deployed along the Thanjavur Coast an 33 Police Check Posts have been set up along the coastal area of the State covering all the known-landing spots. Mobile and foot patrolling has also been introduced in the area. The Central and State Intelligence Agencies have been fully activated and are maintaining close co-ordination in order to curb any militant activity in Tamil Nadu.

Privatisation of Public Sector Units

306. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Governments require any permission from the Central Government for privatising any public sector units under their control;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government are aware that a cement unit and a tractor unit are being privatised in U.P.; and

(d) if so, the deatils thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) to (d) The Department of Public Enterprises does not maintain information regarding the State Governments' public sector enterprises. State Governments, however, do not require permission from the Central Government for privatising public sector units under their control.

औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु मानदण्ड

307. श्री रणजीत सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिये स्थलों के चुनाव का क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ;

(ग) दिसम्बर, 1990 के अन्त में ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे ; और

(घ) शेष सभी विकास केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका): (क) से (घ) सरकार ने पूरे देश में विकास केन्द्र स्थापित करने की एक योजना की जून 1988 में घोषणा की थी। इन विकास केन्द्रों का चुनाव करने के लिए मोटे तौर पर मानदंड यह है कि ये 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 शहरों की परिधि से 50 किलो मीटर, 15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 शहरों की परिधि से 30 किलो मीटर और 7.5 लाख किन्तु 15 लाख से कम जनसंख्या वाले 12 शहरों की परिधि के भीतर नहीं होने चाहिएं। ये विकास केन्द्र जिले/उप मंडलीय/ब्लाक/ताल्लुक मुख्यालय अथवा विकासशील शहरी केन्द्रों के निकट होने चाहिएं और इनकी मूलभूत सुविधानों तक पहुंच होनी चाहिए।

पहले चरण में 70 विकास केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है जिनमें से 61

विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का पहले ही पता लगा लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गई हैं। शेष विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों के लिए प्रस्ताव जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इस योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना

308. **श्री रणजीत सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु वहां औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव था और इस योजना के अधीन कुल कितने धन के व्यय का अनुमान है ;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वियन हेतु आवश्यक धन का प्रावधान किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना धन खर्च करने का प्रस्ताव है और तदनुसार अब तक कुल कितने केन्द्रों की स्थापना की गई थी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये देशभर में 100 विकास केन्द्र स्थापित करने की एक योजना जून, 1988 में घोषित की थी। पहले चरण में 70 विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 61 विकास केन्द्रों के स्थापना स्थल का पता लगा लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गयी है । केन्द्र सरकार ने विकास केन्द्रों के लिये परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं । राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत मूल्यांकन व अनुमोदन किया जायेगा, जिसके बाद निधियां जारी की जायेंगी ।

प्रत्येक विकास केन्द्र को लगभग 25–30 करोड़ रु० की लागत से विकसित किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष 1990 91 में इस योजना के लिए 30 करोड रु० का प्रावधान किया गया है । इस योजना का कार्यान्वयन 8 वीं योजना अवधि के दौरान आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

विनिर्माताओं द्वारा साइकिलों की कीमतों में वृद्धि

309. **श्री रणजीत सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1991 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "पेट्रोल प्राइस हाइक ए बून फार बाइसिकिल कंपनीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि साइकिल विनिर्माताओं ने अपने उत्पादों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने साइकिलों की कीमतों में हुई इस अवांछनीय वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, जुलाई, 1990 से जनवरी 1991 तक की अवधि में साइकिलों के कारखाना बाह्य मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।